राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को उत्तराखण्ड में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार किया। प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुये महंगाई के मुद्दे पर केन्द्र सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि, कांग्रेस ने तय किया है कि यदि हमारी सरकार बनी तो रसोई गैस के दाम 500 रु. से ऊपर नहीं होने दिए जाएंगे।

'बजट सत्र के प्रथम भाग में पैगसस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी'

सरकार और विपक्ष के बीच सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी

नई दिल्ली, 31 जनवरी। केंद्र की मोदी सरकार संसद में पैगसस मुद्दे पर चर्चा कराने को फिलहाल तैयार नहीं है। सोमवार को सभी पार्टियों के साथ बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी।

इसी के साथ एक बात स्पष्ट हो गई है कि मानसून सत्र की तरह ही संसद का बजट सत्र भी हंगामेदार हो सकता है। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ हो गई। सत्र 8 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बीच में एक महीने का ब्रेक भी होगा।

संसद के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा पैगसस स्पाइवेयर का मुद्दा उठाए जाने के संबंध में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि यह मामला विचाराधीन है। उन्होंने कहा, "हमने विपक्ष से कहा है कि बजट सत्र के पहले भाग के दौरान हम केवल बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए, एक अलग चर्चा करना संभव नहीं होगा। मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।"

सोमवार को ऑल-पार्टी मीट के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, "कई पार्टियों ने पैगसस का मुद्दा उठाया है।

हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति मामले की जांच कर रही है। इसलिए (बजट सत्र के पहले भाग में) बजट से संबंधित मुद्दों को ही उठाया जाना चाहिए।" प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज की सर्वदलीय बैठक में 25 दलों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, "सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट सत्र के पहले भाग में केवल राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पेश किया जाता है।"

- **सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, बजट सत्र के पहले भाग में केवल बजट चर्चा और राष्ट्रपति का अभिभाषण कराने की ही परम्परा है।**

'मैंने गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी अंश के, किसी भी तरह से ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म या अन्य किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर प्रदर्शन को निषिद्ध घोषित करने की माँग की गई थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी तथा जे.के. महेश्वरी की बैंच ने कहा कि, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस फिल्म में किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।

बैंच ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि, वे अपनी शिकायत एवं परिवेदन को लेकर उच्च न्यायालय जा सकते हैं क्योंकि लगता है कि उनको इस बात को लेकर भारी चिंता है।

बहल ने प्रतिवादी को ये निर्देश दिये जाने की भी माँग की थी कि, फिल्म की पूरी विषयवस्तु सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से हटा दी जाये। बहल ने कहा कि, फिल्म के निर्माता राष्ट्रपिता पर निशाना साध रहे हैं तथा महात्मा गांधी को बदनाम कर रहे हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय उस समय गये, जब फिल्म निर्माताओं ने 22 जनवरी को इस फिल्म का ट्रेलर सभी लोगों के देखने के लिये जारी कर दिया था।

उन्होंने यह भी माँग की थी कि, फिल्म सैंसर बोर्ड या ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्मों पर रिलीज़ हो रही फिल्मों तथा मीडिया को नियंत्रित करने के लिये खास तौर से बने प्राधिकरण को भी इस संबंध में समुचित निर्देश दिये जायें। याचिका के अनुसार, यह फिल्म कल्याणी सिंह ने राइट्स मीडिया इन्टरनैशनल के बैनर तले बनाई है। यह नाथूराम गोडसे द्वारा की गई महात्मा गांधी की हत्या तथा उससे संबंधित अदालती कार्यवाही पर आधारित है।

याचिका में जोर देकर कहा गया है कि, यह फिल्म महात्मा गांधी की छवि को खराब करने तथा साथ ही नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

देहरादून में डोर-टू-डोर जनसम्पर्क किया पायलट ने

उनके साथ देहरादून में पर्यवेक्षक इंद्राज गुर्जर सहित कई स्थानीय नेता मौजूद थे

देहरादून, 31 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को देहरादून के चुनावी दौरे पर कहा कि साथियों उत्तराखण्ड में चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। हम सभी कांग्रेस जन उत्तराखण्ड वासियों के बीच जाकर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुद्दों को उजागर करना हमारा दायित्व है। जो मुद्दे उत्तराखण्ड के लोगों को छूते हैं, उनको रेखांकित कर सच्चाई बयां करना हमारा काम है। जनता निर्णय करेगी 14 तारीख को और मुझे पूरा भरोसा है सत्ता परिवर्तन का मन उत्तराखण्ड की जनता बना चुकी है।

उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से उत्तराखण्ड के अंदर एक ऐसी सरकार थी, इसका प्रभाव केंद्र में भी था उत्तराखण्ड में भी। सरकार बनाने के बाद भाजपा के नेतृत्व ने लगातार उत्तराखण्ड में बदलाव किया तो जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने दो दो मुख्यमंत्री बदले तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदले, उसके क्या कारण थे। नाकामिया थी, करप्शन था, गर्वनेंस था, क्या मुद्दों को लेकर आपने एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले।

- **पायलट ने कहा, चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने तीन बार मु.मंत्री बदले। सरकार स्थिर नहीं रही, बल्कि जोड़-तोड़ व खींचतान में ही समय निकाला।**

यानी ना तो सरकार स्थिर रही और जोड़-तोड़ और खींचतान में समय निकला। जबकि जनता को मतलब अपने विकास और प्रगति से है। इन 5 सालों में जैसे कि कई मुख्यमंत्री बोलते हैं भाजपा के डबल इंजन की सरकार सरकार है देहरादून और दिल्ली में।

इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो गैस के सिलेंडर के दाम 500 से ज्यादा नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी घोषणा है। आप कल्पना कीजिए जो गैस का सिलेंडर आज 1000,1100 रुपए का मिल रहा , वह क्यों मिल रहा है।

केंद्र में जब भाजपा की सरकार है हमें याद है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो विपक्ष के भाजपा के नेता जब पैट्रोल डिजल के दाम में 25 पैसे बढ़ते थे, तो यह लोग हाहाकार मचाते थे। आज पैट्रोल- डीजल देसी घी से महंगा हो गया। 105-110 पहुंच गया। अब थोड़ी बहुत कटौती की है, जब चुनाव आए हैं। सवाल ये उठता है पैट्रोल-डीजल रसोई गैस सब्जी हर चीज महंगी होने के बावजूद राहत देने का काम सरकार ने नहीं किया।

इससे पहले सचिन पायलट ने देहरादून जाकर पलटन बाजार में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस को जीत दिलाने की अपील की। उनके साथ में देहरादून में पर्यवेक्षक राजस्थान के कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर सहित स्थानीय कांग्रेस नेता भी थे।

कांग्रेस....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभियान को व्यक्तित्व आधारित पहल के रूप में देखा जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जबकि पार्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर है तथा इसे परम्परागत रूप से मिलने वाला जातीय समर्थन बहुत पहले ही छिन्न-भिन्न हो चुका है। यह भी संभावित है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, पार्टी को बिहार में भी "शून्य" से शुरूआत करने की चुनौती का सामना करना पड़े।

बघेल को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होकर भाजपा के पीछे खड़ा हो गया था, जिससे भाजपा को बहुत लाभ हुआ तथा उसकी विधायक संख्या 47 से उछलकर 327 तक पहुँच गई थी। लेकिन इस बार भाजपा के खिलाफ बहुत नाखुशी एवं आक्रोश है। भाजपा चुनाव को हिन्दू बनाम मुस्लिम तक सीमित नहीं कर पाई है। जातियाँ इस चुनाव का महत्वपूर्ण कारक बनी हुई हैं, जो भाजपा के लिये अच्छी खबर नहीं है। बेरोजगारी, कोविड-कुप्रबन्धन, पेट्रोल-डीजल तथा आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि, ब्राह्मण-बनियों की नाराजगी, पिछड़े लोगों द्वारा पार्टी छोड़ना और इन सबसे ऊपर, केन्द्रीय नेतृत्व से आरएसएस की अप्रसन्नता- ये सब कारण मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिये भारी संकट खड़ा कर सकते हैं।

मंत्री मजीठिया की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक

नई दिल्ली, 31 जनवरी (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम राहत देते हुए 23 फरवरी तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मजीठिया की अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें 24 फरवरी को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण और नियमित जमानत के लिए गुहार का मौका दिया।

पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने दलीलें पेश करते हुए कहा मादक पदार्थों की तस्करी के इस धंधे के तार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। इस मामले में भारी मात्रा में रुपयों के लेन-देन हुए हैं, जिसमें मजीठिया ने बिचौलिए का काम किया। आरोपी इस मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यक है। चिदंबरम ने पीठ से कहा कि इतना ही नहीं, यह मामला पंजाब में नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आरोपी मजीठिया की अंतरिम जमानत स्वीकार नहीं की जाए। पीठ ने उनके (पंजाब सरकार) इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए चिदंबरम से कहा कि वह राज्य सरकार को बताएं कि वह कोई ऐसी कार्रवाई न करें जिससे किसी प्रकार से चुनाव पूर्व विरोधियों पर प्रतिशोध कार्रवाई लगे। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोप है कि तस्करी से जुड़े होने के आरोप राजनीति से प्रेरित है।

- **मजीठिया ने कोर्ट में एफिडेविट पेश कर कहा है कि वे, चुनाव होते ही खुद अपनी पेशी कोर्ट के समक्ष दे देंगे।**

ऊषा शर्मा बनीं राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव

जून 2023 में पूरा होगा कार्यकाल

जयपुर, 31 जनवरी (का.प्र.)। प्रदेश की नई प्रसाशनिक मुखिया 1985 बैच की आई.ए.एस. ऊषा शर्मा होंगी। मुख्य सचिव पद से निरंजन आर्य के रिटायर होने के बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए ऊषा शर्मा को प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही ऊषा शर्मा को राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। ऊषा शर्मा प्रदेश की दूसरी ऐसी महिला आई.ए.एस. हैं जो मुख्य सचिव बनी है। इससे पहले 2009 में कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। इसी के साथ कार्मिक विभाग ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। कार्मिक विभाग ने एक साथ दो आदेश जारी करते हुए पहलेप्रदेश के नए मुख्य सचिव के लिए वरिष्ठ आईएएस ऊषा शर्मा के नाम का आदेश जारी किया, वहीं दूसरे आदेश में सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिव निरजंन आर्य का है, जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति के साथ ही मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

- **मुख्य सचिव पद से रिटायर होते ही निरंजन आर्य बने मुख्यमंत्री के सलाहकार।**

ऊषा शर्मा राजस्थान की दूसरी ऐसी महिला आई.ए.एस. हैं जो मुख्य सचिव बनी हैं। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की करीबी रिश्तेदार हैं, वे लम्बे समय से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर थीं।

नवनियुक्त मुख्य सचिव ऊषा शर्मा के पति बीएन शर्मा भी आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें रिटायर होने के बाद राज्य विनियामक आयोग में सदस्य बनाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ऊषा शर्मा के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। ऊषा शर्मा लंबे समय से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थी,जिन्हें राज्य सरकार के आग्रह पर रविवार को ही केंद्र सरकार ने उनके मूल कैडर में भेजने के रिलीव ऑर्डर जारी किए थे। केंद्र से रिलीव होने से पहले 1985 बैच की आईएएस ऊषा शर्मा केंद्र में युवा मामलात मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत थी। इससे पहले वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में महानिदेशक, केंद्रीय एआरडी में अतिरिक्त सचिव और पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन पद पर रह चुकी हैं। पिछली गहलोत सरकार में उषा पर्यटन विभाग में प्रमुख सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा वे यूडीएच सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव, पर्यटन सचिव, उद्योग सचिव, जेडीसी और बूंदी और अजमेर कलेक्टर के रूप में राजस्थान सरकार में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं। इनका सेवा कार्यकाल जून 2023 में पूरा होगा। मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए आईएएस निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री सलाहकार नियुक्त किया गया है। आर्य ने कहा कि जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा। किस विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री देंगे वो उनका अधिकार है, जो भी जिम्मा देंगे उसे पूरा करेंगे। आर्य ने कहा कि, सलाहकार बनने के बाद विभागवार जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके अनुसार योजना क्रियान्विति करेंगे। सीएम के मैंडेट पर गुड गवर्नेंस को आगे बढाएंगे।

'एयर इण्डिया को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में है। भारत की प्रतिक्रिया की एक अन्य विशिष्ट खासियत यह है कि यह प्रतिक्रिया माँग-प्रबन्धन पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, आपूर्ति-पक्ष के सुधारों पर ज्यादा जोर देती है।

स्मृति ईरानी ने छुये मुलायम सिंह के पैर

नई दिल्ली, 31 जनवरी (वार्ता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच संसद से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। बजट सत्र के दौरान सोमवार को मुलायम सिंह यादव संसद की सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी वहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आ गईं। सिंह को देखते ही वह उनकी ओर हाथ जोड़कर बढ़ीं और झुककर उन्हें प्रणाम किया। मुलायम ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद ईरानी खड़े होकर मुलायम के सीढ़ी उतरने का इंतजार करती नजर आईं।

'हम जहां ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

-लाखों रोजगार खत्म हो गये।

-84 प्रतिशत परिवारों की आय बहुत कम हो गई है।

-4.6 करोड़ लोग गरीबी की स्थिति में पहुँच गये हैं।

-वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डैक्स) में भारत 116 देशों में 104 वें स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि, उनकी समझ के अनुसार, "यह समय पश्चाताप तथा (सोच एवं तरीके के) बदलाव के लिये है, डींग हाँकने तथा अपरिवर्तित रहने का नहीं।"

यूनियन बैंक को चौमूं महल टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड से 157.83 करोड़ रूपये वसूलने के आदेश

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 31 जनवरी। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (यू.बी.आई.) को "डेट रिकवरी ट्राइब्यूलन" (डी.आर.टी.) ने "चौमूं महला टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड" और उसके संबंधित एफ.एस. ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड, पंजाब नैशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को भी "चौमूं महला टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड" से लोन का बकाया नहीं दिये जाने की एवज में बड़ी राशि वसूलनी है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को ही इस कम्पनी से 105 करोड़ रूपये वसूलने हैं। डी.आर.टी. के आदेश अनुसार "यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया" द्वारा 157.85 करोड़ की राशि वसूलने के बाद सभी अन्य बैंक भी अपना धन बराबर हिस्सों में वसूल सकते हैं।

- **डैट रिकवरी ट्रिब्युनल (डी.आर.टी.) ने यह आदेश देते हुए व्यवस्था भी दी कि, 157.83 करोड़ की बकाया राशि वसूलने के बाद अन्य बैंक, जिनको कम्पनी से बकाया राशि लेनी है, अपना-अपना धन बराबर हिस्सों में वसूल सकते हैं।**

व्यवसाय में 157.83 करोड़ रूपये वसूलने के आदेश दिये हैं। जयपुर स्थित डी.आर.टी. ने यू.बी.आई. बैंक के मैनेजर द्वारा दायर आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये।

इस मामले में आई.एल. एण्ड एफ.एस. टृस्ट कम्पनी लिमिटेड, पंजाब नैशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को भी "चौमूं महला टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड" से लोन का बकाया नहीं दिये जाने की एवज में बड़ी राशि वसूलनी है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को ही इस कम्पनी से 105 करोड़ रूपये वसूलने हैं। डी.आर.टी. के आदेश अनुसार "यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया" द्वारा 157.85 करोड़ की राशि वसूलने के बाद सभी अन्य बैंक भी अपना धन बराबर हिस्सों में वसूल सकते हैं।

आदेश में बताया गया गया है कि यूनियन बैंक ने इस कम्पनी को बैंक की किश्त व ब्याज नहीं चुकाये जाने की स्थिति में 28 फरवरी 2018 में "नोन परफोरमिग एसिट" (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया था। बैंक ने कई बार इस कम्पनी और इसके मालिकों को ब्याज चुकाने के लिए बोला था, परन्तु 30 अप्रैल 2021 तक कुल बकाया की रकम 157 करोड़ से भी अधिक हो गई थी। डी.आर.टी. ने आदेश दिया है कि इस कम्पनी की "गारंटी" देने वाले दो व्यवसायियों से भी बैंक के कर्ज की राशि वसूली जायेगी। इस मामले में यू.बी.आई. की तरफ से अधिवक्ता शशांक कासलीवाल पेश हुए थे।

आम सभाओं पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से 20 कर दी है। सुरक्षा से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी इनमें नहीं गिने जायेंगे। जहाँ तक हॉल में होने वाली मीटिंगों का प्रश्न है, अब इस तरह की इनडोर मीटिंगों में वर्तमान सीमा 300 को बढ़ाकर 500 या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या एस.डी.एम.ए. द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग के अनुसार रोड शो, पद-यात्रा, जुलूस, साईकिल/ बाइक/ वाहन रैलियाँ 11 फरवरी तक आयोजित की जा सकेंगी। आयोग ने कहा कि 8 जनवरी को व्यापक गाइडलाइन के अन्तर्गत लगाये गये शेष प्रतिबंध यथावत् जारी रहेंगे।

भण्डारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा उच्च न्यायालयों में जज के रुप में नियुक्त किये जाने की सिफारिश की है। कोलिजियम ने न्यायमूर्ति भण्डारी के सम्बंध में अपना निर्णय 14 दिसम्बर को ही ले लिया था जिसे 29 जनवरी दोहराया गया है।

यूक्रेन ने रूस से अपनी सेना वापस बुलाने का आग्रह किया

मॉस्को, 31 जनवरी (वार्ता)। यूक्रेन ने रूस से अनुरोध किया है कि यदि वह युद्ध की स्थिति को बढ़ावा नहीं देने के लिए 'गंभीर' है, तो वह अपनी सीमाओं से अपने सैनिकों को वापस बुलाये और पश्चिमी देशों के साथ अपनी बातचीत जारी रखे।

यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रविवार को कहा, यदि रूसी अधिकारी वास्तव में चाहते हैं कि एक नया युद्ध नहीं हो, तो रूस को राजनयिक संबंध जारी रखना चाहिए और यूक्रेन की सीमाओं और यूक्रेन के अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्रों से सैन्य बलों को वापस बुला लेना चाहिए। कूटनीति ही मसले को हल करने का एकमात्र जिम्मेदार तरीका है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रूस कहता रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है।

भाजपा और अन्नाद्रमुक का गठबंधन बिखर गया

चेन्नई 31 जनवरी (वार्ता)। भाजपा ने सोमवार को तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से नाता तोड़ लिया और राज्य में 19 फरवरी को होने वाले शहरी स्थनीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया।

तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने आगामी शहरी निकाय चुनाव अकेले लड़ने की बात कहते हुए कहा कि अन्नाद्रमुक के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन जारी रहेगा और अन्नाद्रमुक केंद्र की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की सहयोगी रहेगी।

इकोनॉमिक सर्वे इस बार रहस्यमय उलझन है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वित्त में 8.2 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। कृषि और उसके सहयोगी सैक्टर्स वैश्विक महामारी से सबसे कम प्रभावित रहे हैं और इनमें पिछले वर्ष रही 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की तेजी आना अनुमानित है, तथापि यह सैक्टर टैक्स फ्री है। लेकिन, वर्ष 2021-22 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों में भारी इज़ाफे की वापसी हुई है।

वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि मानी गई थी, लेकिन वर्ष 2021 के अप्रैल-नवम्बर माह के दौरान ही इनमें 67.2 प्रतिशत का इजाफा हो गया।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का कलैक्शन भी उत्साहजनक रहा है और जुलाई 2021 से ही जी.एस.टी. का सकल मासिक कलैक्शन 1 लाख करोड़ के पार होता रहा है।

अत: इस प्रश्न का उत्तर जरूरी है कि, राजस्व की रिकवरी कैसे हुई। सर्विस सैक्टर में रिकवरी के लक्षण प्रकट हुए बिना ही जी.एस.टी. कलैक्शन में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से उद्योग एवं निर्माण सैक्टर के महामारी पूर्व के स्तर तक भी ना आने के बावजूद, सरकार की राजस्व प्राप्तियां बढ़ रही हैं।

लेकिन सर्वे के समग्र स्वरूप एवं मूड को देखते हुए, कल आने वाला आम बजट आगामी चुनावों के मद्देनज़र कोई सुखद आश्चर्य और सौगात दे सकता है।

सर्वे अगले वर्ष, यानि की 2022-23 के लिए 8.5 प्रतिशत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि की भविष्यवाणी करता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारत की जी.डी.पी. में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित था, तथापि यह स्मरणीय है कि, यह प्रदर्शन जी.डी.पी. में गत वर्ष रहे संकुचन के बाद का है। अत: यह कुछ हद तक एक "बेस इफैक्ट" है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि के आशावाद का कारण वैक्सिनेशन की व्यापक कवरेज, सप्लाई साइड के सुधारों, नियमनों की सुगमता व निर्यातों की जबर्दस्त वृद्धि से मिले लाभ और परिसम्पत्तियों की खरीद में तेजी लाने के लिए सरकार की वित्तीय नीतियों का लचीलापन है।

सरकार के पास इस सहयोग को बनाए रखने और परिसम्पत्तियों पर किए जाने वाले व्यय को जरूरत पड़ने पर बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षमता है। राजस्व में फिर से आयी मजबूत तेजी अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार को आर्थिक साधन भी उपलब्ध करवाती है।

प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल इसको लेकर आश्वस्त थे कि, वैश्विक महामारी से उपजे आर्थिक संकट और इसके प्रति सरकार की बेहद महत्वपूर्ण और चुस्त प्रतिक्रिया से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक रिकवरी हो सकीं।

सान्याल ने रेखांकित किया कि, वर्ममान संकटों के प्रति घिसी पिटी प्रतिक्रिया देने के बजाए सरकार ने वो उपाय किए जो इस प्रचंड महामारी से उत्पन्न विशेष समस्याओं का मुकाबला करने के लिए थे।

लेकिन, एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि, ऐसे किन्हीं विशेष उपायों की बनिस्पत भारतीय अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित गतिशीलता और इसके अहम खिलाड़ियों ने उसे संकट से उबारा है।

भारत के स्टार्ट अप्स की शानदार आर्थिक वृद्धि के उदाहरण का हवाला दिया जा सकता है, जबकि अधिकांश देश इस मामले में निस्तेज बने हुए हैं।

अमेरिका और चीन के अलावा भारत में सर्वाधिक संख्या में नए स्टार्ट अप हैं और इनके कारोबार में वृद्धि हुई है।

भारत में स्टार्ट अप्स की संख्या पिछले छह वर्षों में प्रमुख रूप से बढ़ी है। वर्ष 2021-22 में नव मान्य स्टार्ट अप्स की संख्या में 14 हजार से अधिक का इजाफा हुआ, जबकि वर्ष 2016-17 में सिर्फ 733 स्टार्ट अप्स ही थे। अमेरिका और चीन के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम बन गया है। इसके अलावा वर्ष 2021 में 44 स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड संख्या में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया, जिसके बाद भारत के यूनिकॉर्न की संख्या 83 हो गई है। इनमें से अधिकांश स्टार्ट अप्स सर्विस सैक्टर के हैं।

भारतीय उद्यमिता का यह मूल ज़ज्बा है, जो कि एक वृहद अर्थव्यवस्था में अपना काम कर रहा है।

कल पेश होने वाले आम बजट का मूल कर्त्तव्य और उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के मनोभाव को समाप्त करना नहीं, बल्कि एक माहौल निर्मित करने में ऐसी सहायता प्रदान करना होना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित गतिशीलता में और मजबूती ला सके।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600